जारी 19/3/19

# कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 1243 / XXV–12(P-7)/2008 देहरादूनः दिनांक 19 मार्च, 2019.

सेवा में,

डॉ0 रवि रस्तोगी,
संस्थापक एवं केन्द्रीय मुख्य संयोजक,
ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोशिएशन
हिमालय एवं हिन्दुस्तान, वीरभद्र
पो. बॉ.नं0, मुख्य डाकघर ऋषिकेश–249201.

**विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या–AIVRWA/RTI/06/2019 दिनांक 12 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत सन्दर्भित सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त संबंध में चाही गयी वांछित सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

| | |
|---|---|
| बिन्दु संख्या–01 | अर्ह मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने हेतु लगातार प्रेषित किया जाता है साथ ही मतदान हेतु प्रेरित किये जाने हेतु SVEEP के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में जनजागरूकता अभियान चलाये जा रहे है। |
| बिन्दु संख्या– 2 | कार्यालय में धारित नही है। |
| बिन्दु संख्या–3 | वोटर कार्ड के अतिरिक्त अन्य 11 दस्तावेजों के पहचान के आधार पर भी वोट डाल सकते है। |
| बिन्दु संख्या–4 | वोटर कार्ड होने से यह सुनिश्चित नही होता कि मतदाता सूची में नाम दर्ज हों। |
| बिन्दु संख्या– 5 | पेड न्यूज संबधी आयोग के पत्र 491 दिनांक 27 अगस्त, 2012 की प्रति कुल 05 पृष्ठ संलग्न है। |
| बिन्दु संख्या–6 | कार्यालय में धारित नही है। |
| बिन्दु संख्या–7 | सोशल मीडिया के संबंध में आयोग के पत्र 491 दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 की कुल 04 पृष्ठ संलग्न है। |
| बिन्दु संख्या– 8 से 12 तक | उक्त सूचना इस कार्यालय में धारित नही है। |

संलग्न– यथोपरि 09 पृष्ठ

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

**विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं**
**सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड**
**विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,**
**सचिवालय परिसर, देहरादून।**

भवदीय,

**(डी0पी0 डंगवाल)**
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

# ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन

(मतदान जनजागरूकता एवं मतदाताओ के हितो और अधिकारो हेतु कार्यरत)

## ALL INDIA VOTERS RIGHTS & WELFARE ASSOCIATION

हिमालय और हिन्दुस्तान, वीरभद्र (ऋषिकेश) 249202
पो.बॉ.नं. 56, मुख्य डाक घर ऋषिकेश - 249 201 देहरादून, उत्तराखण्ड

& hahmedianetwork@gmail.com, himalayaaurhindustan@gmail.com 09897340067

संस्थापक एवं राष्ट्रीय मुख्य संयोजक / अध्यक्ष
डॉ0 रवि स्तोगी
चीफ एडिटर - हिमालय और हिन्दुस्तान

हिमालय और हिन्दुस्तान द्वारा संचालित एवं प्रोत्साहित


क्रमांकः AIVRWA /RTI / 06 / 2019 दिनांकः 12 / 03 / 2019

सेवा में,

**माननीय लोक सूचनाधिकारी महोदय**
**मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड**
**देहरादून**

Y0114

मान्यवर,

सूचनाधिकारी कानून 2005 के अन्तर्गत निम्न जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। नियमानुसार दस रूपये का भारतीय पोस्टल आर्डर 39-F-343108 संलग्न है।

सूचना लेने का हमारा उद्देश्य यह है कि ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एंड वैलफेयर एसोसिएशन विगत चुनावो की भांति इस बार भी सात चरणो में होने वाले 17वीं लोकसभा चुनावो में देशव्यापी निःशुल्क मतदान जनजागरूकता अभियान चला रही है। जिसमे हमें आपके प्रोत्साहन व निम्न जानकारियो की आवश्यकता है।

1. हमारे संलग्न पत्र दिनांक 08.02.2019 पर जो कार्यवाही हुई उसकी जानकारी एवं प्रमाणित प्रति भेजने की कृपा करें।
2. माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून ने यदि कोई प्रत्रोत्तर या संदेश, भेजा हो तो उसकी प्रति भेजने की कृपा करें। हमें अभी तक 08.02.2019 का पत्रोत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आपका संदेश व पत्र हमारे निःशुल्क मतदान जनजागरूकता अभियान को प्रोत्साहित करेगा।
3. जिन मतदाताओ के पास वोटर कार्ड है और लिस्ट में उनका नाम आदि गलत है या फोटो गलत है तो वह मतदाता वोट डाल सकते हैं या नहीं अवगत करायें।
4. जिन मतदाता का वोटर कार्ड है और मतदाता सूची में नाम नहीं है उनके लिए मतदान की जो व्यवस्थाएं या आदेश हैं जानकारी देने की कृपा करें।
5. बहुत से पत्रकार व समाचार पत्र पत्रिका पेड न्यूज से अनभिज्ञ है पेड न्यूज की जानकारी देने एवं पेड न्यूज पर जो कार्यवाही होती है उसकी जानकारी देने की कृपा करें।
6. समाचार पत्र पत्रिका में पार्टी या प्रत्याशी पर लिखा समाचार, फीचर, लेख भी आदि पेड न्यूज के अन्तर्गत आता है उसकी जानकारी देने की कृपा करें। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उसकी प्रति भेजने की कृपा करें।
7. सोशल मीडिया पर जो आचार संहिता लागू है उसकी जानकारी देने की कृपा करें।
8. मतदान सम्बन्धी शिकायत एवं समस्या जहां और जिन नम्बरो पर आपको भेजी जा सकती है उनकी जानकारी देने की कृपा करें।

कृ.प.ऊ. ...

## ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन के कार्य एवं उद्देश्य

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एंड वैलफेयर एसोसिएशन "हिमालय और हिन्दुस्तान" द्वारा मतदान जनजागरूकता एवं मतदाताओ के हितो, अधिकारो हेतु सन् 2006 से संचालित एवं कार्यरत् सर्वदलीय, गैर पंजीकृत और बिना सरकारी सहायता प्राप्त स्वयं सेवी संस्था एवं मिशन है। जिसका मुख्य उद्देश्य माननीय पंचायतों से लेकर संसद तक के सभी चुनावों में मतदाताओ को मतदान हेतु प्रेरित, प्रशिक्षित व प्रोत्साहित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाना एवं शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान हेतु निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारियो, पुलिस प्रशासन को सहयोग देना व उनका सहयोग लेना आदि है।

यदि मतदान करना प्रत्येक मतदाता का कर्त्तव्य और जिम्मेदारी है तो मतदाताओ की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना व सुविधाएं देना केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि पंचायतो से लेकर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारो के निर्माण में मतदाताओ की अहम् भूमिका होती है।

संस्थापक एवं राष्ट्रीय मुख्य संयोजक / अध्यक्ष
डॉ० रवि रस्तोगी
चीफ एडिटर - हिमालय और हिन्दुस्तान

# ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन

(मतदान जनजागरूकता एवं मतदाताओ के हितो और अधिकारो हेतु कार्यरत)

# ALL INDIA VOTERS RIGHTS & WELFARE ASSOCIATION

हिमालय और हिन्दुस्तान, वीरभद्र (ऋषिकेश) 249202
पो.बॉ.नं. 56, मुख्य डाक घर ऋषिकेश - 249 201 देहरादून, उत्तराखण्ड
& hahmedianetwork@gmail.com, himalayaaurhindustan@gmail.com 09897340067


हिमालय और हिन्दुस्तान द्वारा संचालित एवं प्रायोजित

क्रमांक: AIVRWA /RTI / 06 / 2019 दिनांक: 12 / 03 / 2019



9. ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एंड वैलफेयर एसोसिएशन द्वारा हिमालय और हिन्दुस्तान समाचार पत्र एवं मीडिया नेटवर्क (प्रिंट व सोशल न्यूज एजेन्सी) द्वारा निःशुल्क मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। जिसमें पत्रकार, समाचार पत्र पत्रिका, समाजसेवी व मतदाता स्वैच्छिक निःशुल्क सहयोग करते हैं। आपके द्वारा भेजी जानकारिया, समाचार, प्रचार सामग्री, आदि हमारे इस अभियान में संजीवनी का कार्य करेगा। हम मीडिया व जनसहयोग से जगह–जगह मतदान प्रतिज्ञा फार्म भरवाते हैं और चुनाव सम्बन्धी जानकारी, दिशा–निर्देशो से मतदाताओ को अवगत कराते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सअप 9897340067 एवं hahmedianetwork@gmail.com पर जानकारी, प्रचार सामग्री, दिशा–निर्देश चुनाव के दौरान भेजे तो हम उनका सदप्रयोग करेगें।
यदि आपने हमारे 08.02.2019 के बिन्दु 3 के अन्तर्गत भेजना शुरू किया हो तो जानकारी देने की कृपा करे।
हमारा उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के 17वीं लोकसभा 2019 के चुनाव पारदर्शिता दृष्टि से आपके नेतृत्व में देश दुनिया में एक मिसाल पेश करें।

10. होली, नवरात्रा, नूतनवर्ष, ईद आदि पर दलो, अधिकारियो, सरकारी विभागो आदि द्वारा दी गई शुभकामनाएं जिसमें चुनाव सम्बन्धी कुछ न हो यदि वह भी आचार संहिता या पेड न्यूज में आता है तो जानकारी देने की कृपा करें।

11. ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एंड वैलफेयर एसोसिएशन गैर राजनैतिक, गैर पंजीकृत स्वैच्छिक व निःशुल्क मतदान प्रचार–प्रोत्साहन जनजागरूकता अभियान एवं मिशन है। जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओ को मतदान हेतु प्रेरित, प्रोत्साहित व जागरूक करना है। इसमें सहयोगी निःशुल्क व स्वैच्छिक संस्थाएं कई राज्यो में मतदान जनजागरूकता अभियान में देते हैं। कृपया अवगत कराये कि हमें इस अभियान हेतु की जाने वाली नुक्कड़ सभाओ, रैलियो या गोष्ठियां हेतु पुलिस प्रशासन या चुनाव आयोग से स्वीकृति लेने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं।

12. लोकसभा चुनाव में मतदान जनजागरूकता हेतु यदि चुनाव आयोग हमारे सहयोगियो या संस्था की निःशुल्क सेवाएं ले सकता है तो जानकारी देने की कृपा करें। यदि हमें पास या अधिकार पत्र भी मिल सकता है तो उसकी जानकारी देने की कृपा करें और भेजने की कृपा करें।

आपकी जानकारी हमारे मतदान जनजागरूकता अभियान में हमें व हमारे सहयोगियो, मतदाताओ को प्रोत्साहित करेगी।

आप जानकारी पत्र के साथ–साथ हमारे ई–मेल एवं व्हाट्सएप पर भी भेजने की कृपा करें।
लोकसभा चुनाव आपके नेतृत्व में शान्तिपूर्ण व सफलतापूर्वक सम्पनन हो यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है।

6142

डॉ० रवि रस्तोगी
संस्थापक एवं केन्द्रीय मुख्य संयोजक
ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एंड वैलफेयर एसोसिएशन

मो- 9897340067
आधार संख्या- 278252644422

## ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन के कार्य एवं उद्देश्य

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एंड वैलफेयर एसोसिएशन ''हिमालय और हिन्दुस्तान'' द्वारा मतदान जनजागरूकता एवं मतदाताओ के हितो, अधिकारो हेतु सन् 2006 से संचालित एवं कार्यरत् सर्वदलीय, गैर पंजीकृत और बिना सरकारी सहायता प्राप्त स्वयं सेवी संस्था एवं मिशन है। जिसका मुख्य उद्देश्य माननीय पंचायतों से लेकर संसद तक के सभी चुनावों में मतदाताओ को मतदान हेतु प्रेरित, प्रशिक्षित व प्रोत्साहित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाना एवं शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान हेतु निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारियो, पुलिस प्रशासन को सहयोग देना व उनका सहयोग लेना आदि है।

यदि मतदान करना प्रत्येक मतदाता का कर्त्तव्य और जिम्मेदारी है तो मतदाताओ की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना व सुविधाएं देना केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि पंचायतो से लेकर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारो के निर्माण में मतदाताओ की अहम् भूमिका होती है।

# ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन

(मतदान जनजागरूकता एवं मतदाताओ के हितो और अधिकारो हेतु कार्यरत)

## ALL INDIA VOTERS RIGHTS & WELFARE ASSOCIATION

हिमालय और हिन्दुस्तान, वीरभद्र (ऋषिकेश) 249202
पो.बॉ.नं. 56, मुख्य डाक घर ऋषिकेश - 249 201 देहरादून, उत्तराखण्ड

& hahmedianetwork@gmail.com, himalayaaurhindustan@gmail.com 09897340067

*संस्थापक एवं राष्ट्रीय मुख्य संयोजक / अध्यक्ष
डॉ0 रवि रस्तोगी
चीफ एडिटर - हिमालय और हिन्दुस्तान

हिमालय और हिन्दुस्तान द्वारा संचालित एवं प्रोत्साहित


क्रमांकः AIVRWA /02/ 2019 दिनांकः 08 / 02 / 2019

सेवा में,

**माननीय सौजन्या जी**
**मुख्य निर्वाचन अधिकारी**
**उत्तराखण्ड, देहरादून।**

प्रधान.

महोदया,

राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकमनाएं! ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एंड वैलफेयर एसोसिएशन 30 दिसम्बर 2006 से मतदाताओ के हितो व अधिकारो के साथ–साथ मतदाताओ को सभी चुनाव में मतदान हेतु प्रेरित–प्रोत्साहित करती है।

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एंड वैलफेयर एसोसिएशन द्वारा 2017 में उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव एवं 2018 नगर निकाय चुनावो में भी कई जगह मतदाता एवं मतदान जन जागरूकता अभियान चलाया। जिसके प्रमाण संलग्न हैं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके नेतृत्व में उत्तराखण्ड में लोकसभा चुनाव शान्तिपूर्ण सम्पन्न हो तथा मतदान प्रतिशत बढ़े।

महोदया,

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एंड वैलफेयर एसोसिएशन द्वारा अपनी 12वीं वर्षगांठ 30 दिसम्बर 2018 पर आगामी लोकसभा चुनाव तक मतदाता एवं मतदान जनजागरूकता अभियान का शुभारम्भ किया गया है, जो जगह–जगह एक निःस्वार्थ मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। जिसमें जहां मतदाताओ को मतदान हेतु प्रेरित, प्रोत्साहित व जागरूकत किया जा रहा है। वहीं उत्तराखण्ड में शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सफल मतदान हेतु उत्तराखण्ड निर्वाचन विभाग, अधिकारियो, एवं पुलिस प्रशासन को सहयोग देने व सहयोग लेने हेतु भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। निःस्वार्थ यह मतदान जनजागरूकता अभियान आगामी लोकसभा चुनाव तक मीडिया, सोशलमीडिया व संगठनो के सहयोग से चलाया जायेगा।

महोदया,

1. विगत विधानसभा एवं नगर निकाय चुनावो में हमे मतदान हेतु जो जानकारी व समस्याएं पता चली उनमे से अधिकतर मतदाता वोटरकार्ड होने के बावजूद वोटर लिस्ट बनाने वालो की कमी व एक जगह बैठकर लिस्ट सर्वे करने के कारण वोट डालने में वंचित रहे जो उनके मताधिकार का उल्लंघन था।

आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस तरफ विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

कृ.प.उ...

## ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन के कार्य एवं उद्देश्य

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एंड वैलफेयर एसोसिएशन "हिमालय और हिन्दुस्तान" द्वारा मतदान जनजागरूकता एवं मतदाताओ के हितो, अधिकारो हेतु सन् 2006 से संचालित एवं कार्यरत् सर्वदलीय, गैर पंजीकृत और बिना सरकारी सहायता प्राप्त स्वयं सेवी संस्था एवं मिशन है। जिसका मुख्य उद्देश्य माननीय पंचायतों से लेकर संसद तक के सभी चुनावों में मतदाताओ को मतदान हेतु प्रेरित, प्रशिक्षित व प्रोत्साहित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाना एवं शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान हेतु निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारियो, पुलिस प्रशासन को सहयोग देना व उनका सहयोग लेना आदि है।

यदि मतदान करना प्रत्येक मतदाता का कर्त्तव्य और जिम्मेदारी है तो मतदाताओ की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना व सुविधाएं देना केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि पंचायतो से लेकर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारो के निर्माण में मतदाताओ की अहम् भूमिका होती है।

हिमालय और हिन्दुस्तान, वीरभद्र (ऋषिकेश) 249202
पो.बॉ.नं. 56, मुख्य डाक घर ऋषिकेश – 249 201 देहरादून, उत्तराखण्ड
& hahmedianetwork@gmail.com, himalayaaurhindustan@gmail.com 09897340067

संस्थापक एवं राष्ट्रीय मुख्य संयोजक / अध्यक्ष
डॉ0 रवि रस्तोगी
चीफ एडिटर - हिमालय और हिन्दुस्तान


क्रमांक: AIVRWA /02/ 2019 दिनांक: 08 / 02 / 2019



उत्तराखण्ड में शान्तिपूर्ण व सफल मतदान के साथ–साथ मतदान प्रतिशत बढ़ना भी हम सभी का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए जमीनी स्तर से मतदाता एवं मतदान जनजागरूकता अभियान चलाये जाये। स्वयंसेवी संस्थाएं एवं जो व्यक्ति इनमें सहयोग करे उन्हे प्रोत्साहित किया जाये।

2. अधिकतर मीडिया (प्रिंट इलैक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया) आचार संहिता एवं पेड न्यूज से अनभिज्ञ रहते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे मतदान जनजागरूकता अभियान के अन्तर्गत मीडिया के लिए आचार संहिता पेड न्यूज, एवं दण्ड आदि की हिन्दी में जानकारी भेजने की कृपा करें। ताकि मीडिया से जाने अनजाने में होने वाली गलती को रोका जा सके।

3. उत्तराखण्ड निर्वाचन विभाग में हमारा नाम दर्ज कर निःशुल्क जानकारी, प्रचार सामग्री, समाचार, आदि डाक एवं व्हाट्सअप नं. – 9897340067 E-mail hahmedianetwork@gmail.com / himalayaaurhindustan@gmail.com पर भेजने की कृपा करें। हमारे मतदान जनजागरूकता अभियान में पत्रकारो व छोटे समाचार पत्र पत्रिकाओ सहित मीडिया का भी सराहनीय सहयोग व योगदान रहता है।

4. निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा मतदाताओ के लिए मतदान हेतु जो सुविधाएं व योजनाएं बनाई हैं उनकी जानकारी देने की कृपा करें ताकि मतदाताओ तक पहुंचाई जा सके।

इसके साथ मतदाताओ एवं मतदानन सम्बन्धी जानकारी, शिकायते व सुझाव जिन नम्बरो एवं मेल आदि पर दियेजा सके उनकी जानकारी देने की कृपा करें।

आपका प्रोत्साहन पत्र, संदेश एवं सहयोग हमारे निःस्वार्थ मतदाता मतदान जनजागरूकता अभियान में संजीवनी साबित होगा। आपके प्रोत्साहन की प्रतिक्षा में सहयोगाकांक्षी एवं सहयोगी।

भारतीय डाक
India Post

RV732781157IN IVR:82867327[illegible]
RL VIRBHADRA SO (249202)
Counter No:3,25/02/2019,12:07
To:SOJANYA ,D
PIN:248001, Dehradun GPO
From:H AND H ,VBR
Wt:52gms
Amt:32.00(Cash)
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 1800 266 6868)

डॉ0 रवि रस्तोगी
संस्थापक एवं मुख्य संयोजक
मतदाता–मतदान जनजागरूकता अभियान
ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एड वैलफेयर एसोसिएशन


## ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वैलफेयर एसोसिएशन के कार्य एवं उद्देश्य

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एंड वैलफेयर एसोसिएशन "हिमालय और हिन्दुस्तान" द्वारा मतदान जनजागरूकता एवं मतदाताओ के हितो, अधिकारो हेतु सन् 2006 से संचालित एवं कार्यरत् सर्वदलीय, गैर पंजीकृत और बिना सरकारी सहायता प्राप्त स्वयं सेवी संस्था एवं मिशन है। जिसका मुख्य उद्देश्य माननीय पंचायतों से लेकर संसद तक के सभी चुनावों में मतदाताओ को मतदान हेतु प्रेरित, प्रशिक्षित व प्रोत्साहित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाना एवं शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान हेतु निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारियो, पुलिस प्रशासन को सहयोग देना व उनका सहयोग लेना आदि है।

यदि मतदान करना प्रत्येक मतदाता का कर्त्तव्य और जिम्मेदारी है तो मतदाताओं की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना व सुविधाएं देना केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि पंचायतो से लेकर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारो के निर्माण में मतदाताओ की अहम् भूमिका होती है।

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 491/Paid News/2012/Media Dated: 27th August, 2012

To

Chief Electoral Officer of all the States/UTs

Subject:- **Measures to check 'Paid News' during elections i.e. advertisement in garb of news in Media and related matters – revised guidelines – regarding.**

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention to the subject cited and to state that the Commission has issued order No. 509/75/2004/JS-1 dated 15th April, 2004 consequent upon order of the Hon'ble Supreme Court of India in SLP © No. 6679/2004. (Ministry of Information and Broadcasting vs. M/s Gemini TV Pvt. Ltd and Others) requiring the constitution of a committee for previewing, scrutinizing and verifying all advertisements by individual contesting candidates or political parties, before it is inserted in the electronic media. The Commission issued further guidelines vide its letters of even no. dated 8th June 2010, 23rd September 2010, 18th March 2011 and 16th August 2011, to constitute Media Certification and Monitoring Committee (MCMC) in **each district during election period** to take up the additional task of keeping a check on the cases of Paid News.

In modification of orders on 'Paid News' dated 8th June 2010 and thereafter, I am directed to state the following:

**1. District Level Media certification and Monitoring Committee (MCMC)**

1.1 The District level MCMC shall be formed in each district with the following members:

(a) DEO/RO (of Parliamentary Constituency)
(b) ARO(not below SDM)
(c) Central Govt. I & B Ministry official (if any in the district)
(d) Independent Citizen/Journalist as may be recommended by PCI
(e) DPRO/District Information Officer/equivalent - Member Secretary

1.1.1 For the purpose of the certification of advertisements as per aforesaid Supreme Court order, Returning Officer of the parliamentary constituency/District Election Officer and an ARO (not below SDM) shall be the members of the MCMC. However, for the scrutiny of the cases of 'Paid News' etc, District MCMC shall have three additional members as given at 'c', 'd' and 'e'.

1.1.2 If Central govt. I &B Ministry Official is not posted in the district, District Election Officer can appoint preferably a Central Govt. Officer or a senior State Govt. Officer posted in the district.

1.1.2 If PCI is not providing names to be included in the MCMC, DEO may himself appoint either an independent senior citizen or journalist, who is willing and as who, in the opinion of the DEO, is eligible in terms of background and record of neutrality.

1.1.3 The Member Secretary (DPRO/DIO or equivalent) should be from the Provincial State Civil Services.

1.2 The committee shall have two distinct sets of functions:

(i) **Certification of Advertisements** for which two specific members of MCMC i.e. RO & ARO shall have to consider and decide on such advertisements for certification.

(ii) **Examining complaints/issues of Paid News** etc by all members through a monitoring arrangement.

1.3 The MCMC shall, besides discharging the functions of Certification of Advertisement and checking of Paid News, would also assist in enforcement of media related regulations under the RP Act. Hence the Committee's functions shall include:

1.3.1 MCMC shall scan all media ( e.g. newspapers, print media, electronic media, cable network, internet, mobile network etc) for :

a. suspected cases of paid news (it shall also actively consider paid news cases referred to it by the Expenditure Observers. It shall intimate the Returning Officer for issue of notices to candidates for inclusion of actual expenditure on the published matter or **notional expenditure** based on DIPR rates in their election expenses account (in absence of DIPR rates, DAVP rates may be used), either based on or irrespective of whether the candidate actually has paid or not paid any amount to the channel/newspaper. A copy of the notice shall also be marked to Expenditure Observer)

b. monitoring of political advertisements in electronic media (for checking if the telecast/broadcast has been done only after certification by the Committee)

c. monitoring political advertisements in other media, in relation to candidates, either overt or covert, from Expenditure monitoring angle (this will also include publicity or advertisement or appeal by, or on behalf of candidate, or by Star Campaigner(s) or others, to impact candidate's electoral prospects)

d. advertisements in print media (MCMC shall check if the advertisement is with the consent or knowledge of candidate: in which case it will be accounted for in the election expenses of the candidate(s); however, if the advertisement is not with the authority from the candidate, then action may be taken for prosecution of the publisher for violation of Section 171H of IPC)

e. checking if the name and address of the publisher and the printer is carried on any election pamphlet, poster, hand bill and other document as required under Section 127A of R.P.A 1951 (If any printed material does not bear on its face the names and addresses of the printer or the publisher, MCMC shall bring it to the notice of the RO for further necessary action; For the purpose of section 127 of RPA 1951, **'Paid News' would also fall in the category of 'other document')**

1.3.2 It shall submit a daily report to Accounting team with copy to RO and Expenditure Observer in respect of each candidate in the prescribed format (as per annexure 12 of the prescribed Expenditure Guidelines) w.r.t. expenditure incurred by the candidate on election advertising or actual expenditure incurred for publishing the 'News' that is substantiated by necessary documents furnished by the candidate or notional expenditure as computed by the Committee in the assessed cases of Paid News.

1.3.3 The MCMC shall create a suitable mechanism for monitoring media and shall be equipped with adequate manpower and infrastructure for the same.

2. **State level MCMC**

2.1 The State level MCMC shall comprise of the following officers:

(a) The Chief Electoral Officer, Chairman
(b) Any Observer appointed by the Election Commission of India
(c) One expert to be co-opted by the Committee.
(d) Officer of Indian Information Service (IIS), (at the level of US/DS) posted in the State/UT, representing a media Department of Government of India as separate from the expert at (c) above.
(e) Independent citizen or journalist as nominated by PCI (if any)
(f) Addl/Jt CEO in charge of Media (Member Secretary)

2.1.1 If PCI is not providing names to be included in the Committee, CEO may himself appoint either an independent senior citizen or journalist, who is willing and who, in the opinion of the CEO, is eligible in terms of background and record of neutrality.

2.2 The State level MCMC shall perform two sets of functions:

(i) Deciding appeal from both District and Addl/Jt CEO Committees on **Certification of advertisement** as per the aforesaid Commission order dated 15th April 2004.
(ii) **Examining all cases of Paid News** on appeal against the decision of District MCMC or cases that they may take up suo motu, in which case it shall direct the concerned ROs to issue notices to the candidates.

2.2.1 The **appeal on certification** of advertisements need to be handled by members at (a), (b) and (c) in the manner specified in the aforesaid order dated 15th April 2004, while the members at (d), (e) & (f) are added to deal with Paid News cases.

2.2.2 It is clarified that as **regards the certification**, the appeal from both District and Addl/Jt CEO Committee will lie only with and will be disposed of by the State Level MCMC headed by CEO as per Commission's order dated 15th April, 2004 and no reference in this regard needs to be made to the Commission.

**3. Addl/Joint CEO's Committee on Certification :** The Committee chaired by Addl/Jt CEO for **Certification of advertisement,** constituted as per the Commission's 15th April 2004 order shall continue to function as stated in the aforesaid order and shall have no jurisdiction over cases of 'Paid News'.

**4 Appeal against decision of State level MCMC on Paid News**

4.1 Any appeal against the decision of the State level MCMC in matter of Paid News will be made to the Election Commission of India. The State level MCMC can also make a reference to the Commission for advice, if it deems it necessary. Wherever complaints on Paid News cases are made to the Commission directly, the Commission shall forward cases to the State level MCMC for initial consideration.

5. **Paid News Guidelines :** With regard to Paid News, following guidelines may be followed:

5.1 Six months before the due date of normal expiry of Lok Sabha or the State/UT Legislative Assembly, as the case may be, a list of television channels/radio channels/newspapers, broadcast/ circulated in the State/UT and their standard rate cards shall be obtained by the CEOs and provided to all District level MCMCs for fixing the rates of advertisements.

5.2 In case of bye-election to Parliamentary or Assembly constituency, the standard rate card shall be obtained by the District Election Officer concerned immediately on announcement of the bye-election.

5.3 In case of any doubt relating to the application of the standard rate card arising, the matter shall be referred to the DIPR or DAVP, Ministry of I&B, Gov. of India for advice.

5.4 The CEO and DEOs will brief Political Parties and Media Houses about the above guidelines before the commencement of the election campaign. Media shall be asked to exercise self-regulation in this regard. Wide publicity may be given to this order to make the general public also aware about these guidelines. The thrust of the briefing will be on the need for self-regulation.

5.5 The cases of suspected Paid News or advertisement or appeal shall have to be considered within strict timelines as follows:

5.5.1 On reference from District MCMC, RO shall give notice to the candidates within 96 hrs of publication/broadcast/telecast/receipt of complaint to explain/disclose the

expenditure incurred for publishing the 'news' or similar matter, or state why expenditure should not be computed as per standard rate and added to the candidate's expenditure. The same timeline will apply when State level MCMC takes up cases suo motu or on the basis of complaints.

5.5.2 District /State level MCMC shall decide on the reply expeditiously and convey to the Candidate/Party its final decision. In case no reply is received by District MCMC from the candidate within 48 hrs of serving of notice, the decision of MCMC will be final.

5.5.3 If decision of District level MCMC is not acceptable to the candidate, he/she may appeal to State level MCMC within 48 hrs of receipt of decision, with information to the District MCMC.

5.5.4 The State level MCMC shall dispose of the case within 96 hrs of receipt of appeal and convey the decision to the Candidate with a copy to District level MCMC.

5.5.5 The Candidate may appeal against the decision of State level MCMC to ECI within 48 hrs of receiving of order from this Committee. The decision of ECI shall be final.

5.6 The entire process shall ordinarily be completed within Election period.

6. It has been observed that in certain cases, notices on paid news has been issued in large numbers while further action on the same remain pending. MCMCs may ensure that due deliberation takes place on each case and only cases that appear to be suspected cases of 'Paid News' are referred to the RO for issue of notice to the candidate. While seeing that frivolous cases are not taken up, MCMC should ensure that there is no laxity on checking actual 'Paid News'.

7. Where the suspected cases of Paid News are decided as a "Paid News" either at District level/CEO level/Commission level, as the case may be, the actual/notional expenditure shall be treated as part of election expenses of the Candidate concerned, with due intimation to him/her or his/her agent.

7. Where the District/State level Committee or ECI decides that it is a Paid News case, such cases shall be conveyed to Press Council of India for further action in relation to the media concerned.

Yours faithfully,

(Rahul Sharma)
Under Secretary

Copy to: Expenditure Division, Legal Division, ECI

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001.

No. 491/SM/2013/Communication Dated: 25th October, 2013

To,

1. Chief Electoral Officers
   of all States and Union Territories

2. Presidents/General Secretaries
   of All National/State recognized Political Parties.

**Sub: Instructions of the Commission with respect to use of Social Media in Election Campaigning.**

Sir,

The Commission's attention was drawn to use of social media for election campaigning and also certain violations of the Electoral Law in the social media, which need to be regulated in the interest of transparency and level playing field in the elections.

Social media refers to the means of interactions among people in which they create, share, and/or exchange information and ideas in virtual communities and networks. It differentiates from traditional/industrial media in many aspects such as quality, reach, frequency, usability, immediacy, and permanence. The prevalence of Web and social media has increased over the years and there have been demands from the political and social groups to regulate the social media during elections as other media is regulated.

There are broadly five different types of social media:

a) collaborative projects (for example, Wikipedia)

b) blogs and micro blogs (for example, Twitter)

c) content communities (for example, YouTube)

d) social networking sites (for example, Facebook)

e) virtual game-worlds (e.g., Apps)

Legal provisions relating to election campaigning apply to social media in the same manner in which they apply to any other form of election campaigning using any other media. Since social media is a relatively new form of media, it appears necessary to clarify to all concerned by the following instructions:-

**A. <u>Information to be given by candidates about their social media accounts.</u>**

Candidates are required to file affidavits in Form-26 at the time of filing of nominations. Detailed instructions and the format in which the affidavits have

to be filled were issued vide the Commission's letter No. 3/4/2012/SDR dated 24, August, 2012. Para 3 of this Form requires that email ID of the candidate, if any, should be communicated to the Commission in this Form. The Commission finds it necessary that authentic social media accounts of candidates should also be informed to the Commission. This information should be furnished in the said Para 3 as follows:-

"My contact telephone no.(s) is/are.....,
my email ID (if any) is ....., and
my social media accounts (if any) are....."

**B. Pre-Certification of Political Advertisements**

In pursuance of the Hon'ble Supreme Court of India's Order in SLP (Civil) N. 6679/2004, dated 13 April,2004, the Commission issued detailed instructions on this subject vide its order no. 509/75/2004/JS-1/4572 dated 15.04.2004. In this order, it was stated that every registered/national and State political party and every contesting candidate proposing to issue advertisements on television channels and/ or on cable network will have to apply to Election Commission of India/designated officer for pre-certification of all political advertisements on electronic media before the publication. The order was further modified and consolidated vide Commission's order dated 27.08.2012, wherein Media Certification and Monitoring Committees at district and State levels were given the responsibilities of pre-certification of such advertisement along with other functions viz acting against Paid News etc. Since social media websites are also electronic media by definition, therefore, these instructions of the Commission contained in its order No.509/75/2004/JS-1/4572 dated 15.04.2004 shall also apply mutatis mutandis to websites including social media websites and shall fall under the purview of pre-certification. You are, therefore, requested to ensure that no political advertisements are released to any internet based media/websites, including social media websites, by political parties/candidates without pre-certification from competent authorities in the same format and following the same procedures as referred in the aforesaid orders.

**C. Expenditure on campaigning through internet including social media websites.**

According to Section 77, sub section (1), of Representation of the People Act, 1951, every candidate is required to keep a separate and correct account of all

ways to deal with the issue, in so far as they relate to, or can be reasonably connected with, the election campaigning of political parties and candidates.

These instructions may please be brought to the notice of all concerned including candidates, political parties, media and election observers for immediate necessary action.

Yours faithfully,

Sd/-

(Rahul Sharma)
(Under Secretary)
Tel. 011-23052070
Email: rahulsharma.eci@gmail.com

expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he has filed nomination and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive. The Hon'ble Supreme Court of India had directed in Common Cause Vs. Union of India in 2005 that political parties should also submit a statement of expenditure of elections to the ECI and such statements are required to be submitted within 75 days of assembly elections and 90 days of Lok Sabha elections. It is obvious that expenditure on election campaign through any advertisement in social media is a part of all expenditure in connection with the elections.

For the sake of removing any ambiguity, it is hereby directed that candidates and political parties shall include all expenditure on campaigning, including expenditure on advertisements on social media, both for maintaining a correct account of expenditure and for submitting the statement of expenditure. This, among other things, shall include payments made to internet companies and websites for carrying advertisements and also campaign related operational expenditure on making of creative development of content, operational expenditure on salaries and wages paid to the team of workers employed by such candidates and political parties to maintain their social media accounts, etc.

**D. Application of Model Code of Conduct to content on internet including social media.**

The Commission has a model code of conduct in place during the elections in respect of political parties and candidates which remains in force from the date the elections are announced by the Commission till the completion of elections. It is clarified that the provisions of model code of conduct and related instructions of the Commission issued from time to time shall also apply to the content being posted on the internet, including social media websites, by candidates and political parties.

**E.** As far as the content posted by persons other than candidates and political parties is concerned, the Commission is considering the matter in consultation with the Ministry of Communication and Information Technology on practical